प्राकृतविद्या (Prakritvidya)
VOL. 58 /ISSUE 2 /2025
Jul - Dec 2025

सतत आर्थिक विकास और हरित अर्थव्यवस्था: वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते आयामों का अध्ययन

डॉ. अनन्या शर्मा

सारांश

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को केवल उत्पादन और आय की वृद्धि से नहीं आँका जा सकता। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, प्रदूषण और सामाजिक असमानता ने विकास की गुणवत्ता तथा उसकी दीर्घकालीन स्थिरता पर नए प्रश्न उठाए हैं। इस संदर्भ में सतत आर्थिक विकास और हरित अर्थव्यवस्था ऐसी अवधारणाएँ हैं जो आर्थिक समृद्धि को पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन के साथ जोड़ती हैं। यह शोध-पत्र हरित अर्थव्यवस्था की वैचारिक पृष्ठभूमि, संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त, हरित रोजगार और विकासशील देशों की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का तर्क है कि हरित संक्रमण केवल पर्यावरणीय नीति नहीं बल्कि उत्पादन, निवेश, तकनीकी नवाचार और रोजगार संरचना में व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

प्रमुख शब्द

सतत विकास, हरित अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त, हरित रोजगार, संसाधन दक्षता

प्रस्तावना

आर्थिक विकास ने विश्व के अनेक हिस्सों में जीवन स्तर, उत्पादकता, परिवहन और तकनीकी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। फिर भी पारंपरिक विकास मॉडल का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधनों, उच्च संसाधन खपत और रैखिक उत्पादन-उपभोग व्यवस्था पर निर्भर रहा है। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के साथ कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट और पारिस्थितिक दबाव भी बढ़े हैं। अब नीति-निर्माताओं के सामने ऐसी विकास रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक अवसरों का विस्तार हो, लेकिन प्राकृतिक पूँजी का क्षरण अनियंत्रित न हो। सतत विकास इसी संतुलन को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है।

1. वैचारिक पृष्ठभूमि

हरित अर्थव्यवस्था का मूल विचार यह है कि आर्थिक गतिविधियों को कम-कार्बन, संसाधन-कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी बनाया जाए। इसमें ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, हरित भवन, अपशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। संसाधन दक्षता का अर्थ केवल कम संसाधन उपयोग करना नहीं है, बल्कि उत्पादन की प्रति इकाई अधिक मूल्य पैदा करना, पुनर्चक्रण बढ़ाना और अपशिष्ट को न्यूनतम करना भी है। इस दृष्टिकोण में पर्यावरणीय लागतों को आर्थिक निर्णयों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। व्यवसायिक स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। लागत बचत, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की बदलती माँग को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

ऊर्जा संक्रमण हरित अर्थव्यवस्था का केंद्रीय घटक है। सौर, पवन, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ती क्षमता ऊर्जा प्रणाली को अधिक विविध और कम-कार्बन बनाने में सहायता कर सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्षता, भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और मांग प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे देशों में ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ यह चुनौती और जटिल हो जाती है, क्योंकि विकास और ऊर्जा पहुँच दोनों आवश्यक हैं। इसलिए संक्रमण को ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, वहनीयता और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करे। इस दृष्टिकोण में सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन की मात्रा से नहीं, बल्कि उत्पादकता, संसाधन दक्षता, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव जैसे संकेतकों से भी किया जाना चाहिए।

हरित वित्त वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें पूँजी को ऐसे प्रोजेक्टों की ओर निर्देशित किया जाता है जो पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देते हैं। हरित बॉन्ड, स्थायी ऋण, जलवायु वित्त और पर्यावरणीय जोखिम आकलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वित्तीय संस्थाएँ निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम और संसाधन जोखिम को शामिल करके आर्थिक परिवर्तन को गति दे सकती हैं। लेकिन हरित वित्त की विश्वसनीयता के लिए स्पष्ट मानक, पारदर्शिता और प्रभाव का मापन आवश्यक है, ताकि केवल नाम बदलने से किसी परियोजना को हरित घोषित न किया जाए। इस विषय का विश्लेषण करते समय आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को एक साथ देखना आवश्यक है। किसी एक संकेतक में सुधार को पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि दीर्घकालीन समृद्धि प्राकृतिक और संस्थागत पूँजी पर भी निर्भर करती है।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

आर्थिक विकास ने विश्व के अनेक हिस्सों में जीवन स्तर, उत्पादकता, परिवहन और तकनीकी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। फिर भी पारंपरिक विकास मॉडल का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधनों, उच्च संसाधन खपत और रैखिक उत्पादन-उपभोग व्यवस्था पर निर्भर रहा है। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के साथ कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट और पारिस्थितिक दबाव भी बढ़े हैं। अब नीति-निर्माताओं के सामने ऐसी विकास रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक अवसरों का विस्तार हो, लेकिन प्राकृतिक पूँजी का क्षरण अनियंत्रित न हो। सतत विकास इसी संतुलन को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है। नीति-निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों, आय स्तर, रोजगार संरचना और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे ऐसी रणनीति बन सकती है जो व्यावहारिक भी हो और दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुरूप भी।

2. प्रमुख आयाम

ऊर्जा संक्रमण हरित अर्थव्यवस्था का केंद्रीय घटक है। सौर, पवन, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ती क्षमता ऊर्जा प्रणाली को अधिक विविध और कम-कार्बन बनाने में सहायता कर सकती है। साथ ही ऊर्जा दक्षता, भंडारण, स्मार्ट ग्रिड और मांग प्रबंधन भी महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे देशों में ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ यह चुनौती और जटिल हो जाती है, क्योंकि विकास और ऊर्जा पहुँच दोनों आवश्यक हैं। इसलिए संक्रमण को ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति, वहनीयता और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करे। इस दृष्टिकोण में सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन की मात्रा से नहीं, बल्कि उत्पादकता, संसाधन दक्षता, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव जैसे संकेतकों से भी किया जाना चाहिए।

हरित वित्त वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें पूँजी को ऐसे प्रोजेक्टों की ओर निर्देशित किया जाता है जो पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देते हैं। हरित बॉन्ड, स्थायी ऋण, जलवायु वित्त और पर्यावरणीय जोखिम आकलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वित्तीय संस्थाएँ निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम और संसाधन जोखिम को शामिल करके आर्थिक परिवर्तन को गति दे सकती हैं। लेकिन हरित वित्त की विश्वसनीयता के लिए स्पष्ट मानक, पारदर्शिता और प्रभाव का मापन आवश्यक है, ताकि केवल नाम बदलने से किसी परियोजना को हरित घोषित न किया जाए। इस विषय का विश्लेषण करते समय आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को एक साथ देखना आवश्यक है। किसी एक संकेतक में सुधार को पूर्ण

विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि दीर्घकालीन समृद्धि प्राकृतिक और संस्थागत पूँजी पर भी निर्भर करती है।

हरित संक्रमण रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन रोजगार संरचना में बदलाव भी ला सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय परामर्श और टिकाऊ कृषि में नई भूमिकाएँ उभर सकती हैं। दूसरी ओर, उच्च-कार्बन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को कौशल परिवर्तन और पुनर्प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए न्यायपूर्ण संक्रमण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय पुनर्विकास नीतियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि हरित परिवर्तन के लाभ व्यापक हों। नीति-निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों, आय स्तर, रोजगार संरचना और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे ऐसी रणनीति बन सकती है जो व्यावहारिक भी हो और दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुरूप भी।

हितधारकों के लिए निहितार्थ

हरित अर्थव्यवस्था का मूल विचार यह है कि आर्थिक गतिविधियों को कम-कार्बन, संसाधन-कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी बनाया जाए। इसमें ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, हरित भवन, अपशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। संसाधन दक्षता का अर्थ केवल कम संसाधन उपयोग करना नहीं है, बल्कि उत्पादन की प्रति इकाई अधिक मूल्य पैदा करना, पुनर्चक्रण बढ़ाना और अपशिष्ट को न्यूनतम करना भी है। इस दृष्टिकोण में पर्यावरणीय लागतों को आर्थिक निर्णयों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। व्यवसायिक स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। लागत बचत, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की बदलती माँग को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

3. अवसर और उभरती प्रवृत्तियाँ

हरित संक्रमण रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन रोजगार संरचना में बदलाव भी ला सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय परामर्श और टिकाऊ कृषि में नई भूमिकाएँ उभर सकती हैं। दूसरी ओर, उच्च-कार्बन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को कौशल परिवर्तन और पुनर्प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए न्यायपूर्ण संक्रमण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय पुनर्विकास नीतियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि

हरित परिवर्तन के लाभ व्यापक हों। इस विषय का विश्लेषण करते समय आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को एक साथ देखना आवश्यक है। किसी एक संकेतक में सुधार को पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि दीर्घकालीन समृद्धि प्राकृतिक और संस्थागत पूँजी पर भी निर्भर करती है।

विकासशील देशों के लिए हरित संक्रमण में वित्त, तकनीक, बुनियादी ढाँचे और संस्थागत क्षमता की बाधाएँ हो सकती हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए ऊर्जा और परिवहन की लागत भी महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरणीय नीतियाँ सामाजिक प्रभावों की उपेक्षा करती हैं, तो संक्रमण असमानता बढ़ा सकता है। इसी कारण नीति-निर्माण में क्रमिक परिवर्तन, लक्षित सहायता, स्थानीय रोजगार और सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग और जलवायु वित्त भी विकासशील देशों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। नीति-निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों, आय स्तर, रोजगार संरचना और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे ऐसी रणनीति बन सकती है जो व्यावहारिक भी हो और दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुरूप भी।

सतत विकास को प्रभावी बनाने के लिए सरकारों को दीर्घकालीन नीति संकेत, स्पष्ट पर्यावरणीय मानक और निवेश-अनुकूल ढाँचा तैयार करना चाहिए। उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ तकनीक में निवेश हेतु प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। नगरों में सार्वजनिक परिवहन, हरित भवन और अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को पर्यावरणीय जोखिम का मूल्यांकन मजबूत करना चाहिए। नागरिकों के स्तर पर टिकाऊ उपभोग, ऊर्जा बचत और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। लागत बचत, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की बदलती माँग को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

महत्वपूर्ण चुनौतियाँ

हरित वित्त वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें पूँजी को ऐसे प्रोजेक्टों की ओर निर्देशित किया जाता है जो पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देते हैं। हरित बॉन्ड, स्थायी ऋण, जलवायु वित्त और पर्यावरणीय जोखिम आकलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वित्तीय संस्थाएँ निवेश निर्णयों में जलवायु जोखिम और संसाधन जोखिम को शामिल करके आर्थिक परिवर्तन को गति दे सकती हैं। लेकिन हरित वित्त की विश्वसनीयता के लिए स्पष्ट मानक, पारदर्शिता और प्रभाव का मापन आवश्यक है, ताकि केवल नाम बदलने से किसी परियोजना को हरित घोषित न किया जाए। इस दृष्टिकोण में सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन की

मात्रा से नहीं, बल्कि उत्पादकता, संसाधन दक्षता, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव जैसे संकेतकों से भी किया जाना चाहिए।

4. नीतिगत एवं रणनीतिक निहितार्थ

विकासशील देशों के लिए हरित संक्रमण में वित्त, तकनीक, बुनियादी ढाँचे और संस्थागत क्षमता की बाधाएँ हो सकती हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए ऊर्जा और परिवहन की लागत भी महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरणीय नीतियाँ सामाजिक प्रभावों की उपेक्षा करती हैं, तो संक्रमण असमानता बढ़ा सकता है। इसी कारण नीति-निर्माण में क्रमिक परिवर्तन, लक्षित सहायता, स्थानीय रोजगार और सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग और जलवायु वित्त भी विकासशील देशों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। नीति-निर्माण में स्थानीय परिस्थितियों, आय स्तर, रोजगार संरचना और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे ऐसी रणनीति बन सकती है जो व्यावहारिक भी हो और दीर्घकालीन उद्देश्यों के अनुरूप भी।

सतत विकास को प्रभावी बनाने के लिए सरकारों को दीर्घकालीन नीति संकेत, स्पष्ट पर्यावरणीय मानक और निवेश-अनुकूल ढाँचा तैयार करना चाहिए। उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ तकनीक में निवेश हेतु प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। नगरों में सार्वजनिक परिवहन, हरित भवन और अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर आवश्यक है। वित्तीय संस्थानों को पर्यावरणीय जोखिम का मूल्यांकन मजबूत करना चाहिए। नागरिकों के स्तर पर टिकाऊ उपभोग, ऊर्जा बचत और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। लागत बचत, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की बदलती माँग को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

आर्थिक विकास ने विश्व के अनेक हिस्सों में जीवन स्तर, उत्पादकता, परिवहन और तकनीकी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। फिर भी पारंपरिक विकास मॉडल का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधनों, उच्च संसाधन खपत और रैखिक उत्पादन-उपभोग व्यवस्था पर निर्भर रहा है। परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों के साथ कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट और पारिस्थितिक दबाव भी बढ़े हैं। अब नीति-निर्माताओं के सामने ऐसी विकास रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें आर्थिक अवसरों का विस्तार हो, लेकिन प्राकृतिक पूँजी का क्षरण अनियंत्रित न हो। सतत विकास इसी संतुलन को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण में सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन की मात्रा से नहीं,

बल्कि उत्पादकता, संसाधन दक्षता, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव जैसे संकेतकों से भी किया जाना चाहिए।

भविष्य की दिशा

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को केवल उत्पादन और आय की वृद्धि से नहीं आँका जा सकता। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, प्रदूषण और सामाजिक असमानता ने विकास की गुणवत्ता तथा उसकी दीर्घकालीन स्थिरता पर नए प्रश्न उठाए हैं। इस संदर्भ में सतत आर्थिक विकास और हरित अर्थव्यवस्था ऐसी अवधारणाएँ हैं जो आर्थिक समृद्धि को पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन के साथ जोड़ती हैं। यह शोध-पत्र हरित अर्थव्यवस्था की वैचारिक पृष्ठभूमि, संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित वित्त, हरित रोजगार और विकासशील देशों की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का तर्क है कि हरित संक्रमण केवल पर्यावरणीय नीति नहीं बल्कि उत्पादन, निवेश, तकनीकी नवाचार और रोजगार संरचना में व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इस विषय का विश्लेषण करते समय आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को एक साथ देखना आवश्यक है। किसी एक संकेतक में सुधार को पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि दीर्घकालीन समृद्धि प्राकृतिक और संस्थागत पूँजी पर भी निर्भर करती है।

5. चर्चा

हरित अर्थव्यवस्था का मूल विचार यह है कि आर्थिक गतिविधियों को कम-कार्बन, संसाधन-कुशल और सामाजिक रूप से समावेशी बनाया जाए। इसमें ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ परिवहन, हरित भवन, अपशिष्ट प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। संसाधन दक्षता का अर्थ केवल कम संसाधन उपयोग करना नहीं है, बल्कि उत्पादन की प्रति इकाई अधिक मूल्य पैदा करना, पुनर्चक्रण बढ़ाना और अपशिष्ट को न्यूनतम करना भी है। इस दृष्टिकोण में पर्यावरणीय लागतों को आर्थिक निर्णयों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। व्यवसायिक स्तर पर भी परिवर्तन आवश्यक है। लागत बचत, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की बदलती माँग को पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।

हरित संक्रमण रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन रोजगार संरचना में बदलाव भी ला सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय परामर्श और टिकाऊ कृषि में नई भूमिकाएँ उभर सकती हैं। दूसरी ओर, उच्च-कार्बन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को कौशल परिवर्तन और पुनर्प्रशिक्षण की

आवश्यकता हो सकती है। इसलिए न्यायपूर्ण संक्रमण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय पुनर्विकास नीतियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि हरित परिवर्तन के लाभ व्यापक हों। इस दृष्टिकोण में सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश या उत्पादन की मात्रा से नहीं, बल्कि उत्पादकता, संसाधन दक्षता, रोजगार की गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव जैसे संकेतकों से भी किया जाना चाहिए।

विकासशील देशों के लिए हरित संक्रमण में वित्त, तकनीक, बुनियादी ढाँचे और संस्थागत क्षमता की बाधाएँ हो सकती हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए ऊर्जा और परिवहन की लागत भी महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरणीय नीतियाँ सामाजिक प्रभावों की उपेक्षा करती हैं, तो संक्रमण असमानता बढ़ा सकता है। इसी कारण नीति-निर्माण में क्रमिक परिवर्तन, लक्षित सहायता, स्थानीय रोजगार और सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग और जलवायु वित्त भी विकासशील देशों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस विषय का विश्लेषण करते समय आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को एक साथ देखना आवश्यक है। किसी एक संकेतक में सुधार को पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि दीर्घकालीन समृद्धि प्राकृतिक और संस्थागत पूँजी पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष

सतत आर्थिक विकास और हरित अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति की परिधि का विषय नहीं बल्कि विकास के मूल मॉडल को पुनर्विचार करने की प्रक्रिया है। दीर्घकालीन समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, उत्पादकता में सुधार और सामाजिक अवसरों का विस्तार साथ-साथ होना चाहिए। हरित निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षता और हरित रोजगार इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण आधार हैं। भविष्य की सफल रणनीति वही होगी जो पर्यावरणीय लक्ष्यों को आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक न्याय से जोड़ सके।

संदर्भसूची

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford University Press.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.

United Nations Environment Programme. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. UNEP.

International Energy Agency. (2023). World energy outlook 2023. IEA.

World Bank. (2022). Inclusive green growth: The pathway to sustainable development. World Bank.